

आइ० आर० की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों से ज्ञात की जा रही है।

(ग) उपलब्ध रिकार्ड से यह देखा जा सकता है कि जनवरी 1980 से फरवरी 1984 तक की अवधि में भर्ती-नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। यदि कोई विशिष्ट मामला सी०एस० आइ०आर० की जानकारी में लाया जाता है तो उस पर तुरन्त गौर किया जायेगा।

**Proposal to Restore Sick Units to Health**

5174. SHRI MADHAVRAO SCIENDIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the appeal issued by the President of the Employees Federation of India urging Government to explore 'urgently' alternatives other than takeover to restore sick units to health;

(b) if so, the Government's reaction thereto; and

(c) the details of sick mills presently under Government's view and what steps are being contemplated to restore health to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI PATTABHI RAMA RAO): (a) Yes, Sir,

(b) According to the existing policy on sick industries, banks and financial institutions examine, on the basis of diagnostic study, whether a sick unit can be revived through appropriate measures. They also attempt to explore other solutions like takeover of sick units by healthy companies. If these efforts are unlikely to revive the sick unit, the Government consider if the unit should be nationalised or any other alternative can revive the undertaking. When no solution is considered feasible, the banks and financial institutions recover their dues from the undertakings as per the normal banking procedures.

(c) According to the data (provisional) collected by the Reserve Bank of India, there was 450 large (each with credit limit of Rs. one crore and above) sick industrial

units as at the end of December, 1982. In October, 1981, the Government announced revised policy on industrial sickness for the guidance of Central Ministries, State Governments and financial institutions. The salient features of the guidelines were furnished in reply to the Lok Sabha Unstarred Question No. 4974 on 24th March, 1982.

पश्चिम चम्पारण बिहार में नमक का अभाव

5175. श्री जगपाल सिंह :

स्वामी इन्द्रवेश :

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "लासों लोग नमक नमक को तरसें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण तथा निकटवर्ती इलाकों में नमक अभाव तथा दुकानों से प्राप्त नमक में आयोडीन का न पाया जाना जिससे घंघा, रतौदी, मन्द मानसिक विकास आदि बिमारियों का बहुतायत में होने आदि मुद्दों पर विचार कर सुगमता से नमक उपलब्ध कराए जाने हेतु कारगर कार्यवाही की जाएगी; और

(ग) क्या नमक की ब्लैक में बिक्री को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की है तथा इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हाँ।

बिहार सरकार से बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिले में आणोडीकृति नमक कमी के बारे में कुछ समाचार मिले हैं। जनवरी-फरवरी, 1984 में नमक की कम सप्लाई मुख्यतः इस कारण हुई थी कि राज्य सरकार के नामित व्यक्तियों ने केवल 3,622 मी० टन नमक के लिए निविदाएं भेजी थीं; जबकि इस